

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 4 ]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 28 जनवरी 2022—माघ 8, शक 1943

### विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

## भाग १

### राज्य शासन के आदेश

#### सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 16 नवम्बर 2021

क्रमांक ई 1-01/2021/एक-2.—राज्य शासन एतद्वारा श्री डी. राहुल वेंकट, भा.प्र.से. (2015), उप सचिव तथा विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ महाप्रबंधक (प्रशासन), छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
कमलप्रीत सिंह, सचिव.

**गृह (पुलिस) विभाग**  
**मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर**

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 15 दिसम्बर 2021

क्रमांक एफ-7-02/2021/दो-गृह/भापुसे.—राज्य शासन एतद्वारा श्री प्रखर पाण्डेय (भापुसे-2009), सेनानी, 6वीं वाहिनी, छसबल, रायगढ़, छत्तीसगढ़ को दिनांक 15 दिसम्बर 2021 से 24 दिसम्बर 2021 (कुल 10 दिवस) तक का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही दिनांक 25 एवं 26 दिसम्बर 2021 के विज्ञप्त शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

2. अवकाश से लौटने पर श्री पाण्डेय (भापुसे-2009), सेनानी, 6वीं वाहिनी, छसबल, रायगढ़, छत्तीसगढ़ के पद पर पुनः पदस्थ होंगे।
3. अवकाश काल में श्री पाण्डेय (भापुसे) को अवकाश वेतन, भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्व मिलते थे।
4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पाण्डेय (भापुसे) अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।
5. श्री प्रखर पाण्डेय (भापुसे-2009), सेनानी, 6वीं वाहिनी, छसबल, रायगढ़, छत्तीसगढ़ के उक्त अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री के. एल. ध्रुव, (भापुसे-2008), सेनानी, 2रीं वाहिनी, छसबल, बिलासपुर, छ.ग. को उनके वर्तमान कार्य के साथ-साथ सौंपा जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**मनोज श्रीवास्तव**, अवर सचिव.

**कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग**  
**मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर**

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 30 नवम्बर 2021

क्रमांक/5904/एफ-11/06/2020/14-2.—छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 17 की उप-धारा (2) के खण्ड (उन्नीस) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, कृषि उपज मण्डी समितियों के मण्डी प्रांगण/उपमण्डी प्रांगण में तुलैयों तथा हमालों द्वारा किये जाने वाले कार्यों के लिए, कार्यवार निम्नानुसार न्यूनतम पारिश्रमिक दर निर्धारित करती है :—

स.क्र. (1)	कार्य (2)	दर प्रति क्विंटल (रु. में) (3)
1.	अनलोडिंग	2.75
2.	ढेर लगाना	1.40
3.	बोरा भराई	2.60
4.	तौल	2.60
5.	सिलाई	1.40
6.	लेबलिंग	1.25

(1)	(2)	(3)
7.	लोडिंग	4.80
8.	स्टैकिंग लेबलिंग के साथ	3.00

ये दरें, दिनांक 01-04-2021 से आगामी आदेश तक के लिए प्रभावशील होंगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
के. सी. पैकरा, संयुक्त सचिव.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 30 नवम्बर 2021

क्रमांक/एफ-11/06/2020/14-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक/5904/रायपुर, दिनांक 30-11-2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
के. सी. पैकरा, संयुक्त सचिव.

Nava Raipur, 30th November 2021

No./5904/F-11/06/2020/14-2.—In exercise of the powers conferred by clause (xix) of sub-section (2) of Section 17 of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government, hereby, determines the work-wise minimum wages rate for the work done by weighman and Hammal in the market yard/sub-market yard of Agricultural Produce Market Committees, as follows :—

No. (1)	Work (2)	Rate per quintal (Rs.) (3)
1.	Unloading	2.75
2.	Heap Up	1.40
3.	Bagging	2.60
4.	Weighing	2.60
5.	Stitching	1.40
6.	Labelling	1.25
7.	Loading	4.80
8.	Staking with labelling	3.00

These rates shall be effective from 01-04-2021 till further order.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,  
K. C. PAIKARA, Joint Secretary.

**राजस्व विभाग**

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़ (छत्तीसगढ़), एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,  
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

रायगढ़, दिनांक 6 दिसम्बर 2021

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 202111042100049/अ-82/2021-22.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची				धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	भाठनपाली प.ह.नं. 09	0.095	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़ जिला-रायगढ़ (छ.ग.).	केलो परियोजना के अंतर्गत टेंगापाली वितरक नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 6 दिसम्बर 2021

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 202111042100050/अ-82/2021-22.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची				धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	छातामुड़ा प.ह.नं. 06	0.187	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़ जिला-रायगढ़ (छ.ग.).	केलो परियोजना के अंतर्गत छातामुड़ा, सहदेवपाली एवं नन्हईडीपा माइनर नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 6 दिसम्बर 2021

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 202111042100051/अ-82/2021-22.—चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची				धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	गढ़उमरिया प.ह.नं. 07	0.182	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़ जिला-रायगढ़ (छ.ग.).	केलो परियोजना के अंतर्गत बड़ेडोरा, अघरियापारा, नन्हाईडीपा, लघु नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**भीम सिंह**, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छत्तीसगढ़), एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,  
 राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

उत्तर बस्तर कांकेर, दिनांक 22 नवम्बर 2021

क्रमांक/6333/भू-अर्जन/201806141400005/अ-82/2017-18.—चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची				धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	कांकेर	मनकेसरी प.ह.नं. 30	0.40	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, कांकेर.	ग्राम मनकेसरी के उलटवियर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा)/भू-अर्जन अधिकारी, कांकेर जिला उत्तर बस्तर कांकेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

उत्तर बस्तर कांकेर, दिनांक 22 नवम्बर 2021

क्रमांक/6334/भू-अर्जन/202007141400009/अ-82/2019-20.—चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	नरहरपुर	बागोड़ प.ह.नं. 17	0.41	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, कांकेर.	बागोड़ महानदी पर एनीकट/केनाल निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा)/भू-अर्जन अधिकारी, कांकेर जिला उत्तर बस्तर कांकेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
चंदन कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ एवं  
पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

खसरा नम्बर  
(1)  
रकबा  
(हेक्टेयर में)  
(2)

जशपुर, दिनांक 23 नवम्बर 2021

382 0.032

370/1 0.032

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 02/अ-82/2019-20.—चूँकि राज्य

369/1 0.016

शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

477/3 0.032

369/2 0.012

477/4 0.032

368 0.048

367/2 0.008

433/1क 0.096

357 0.016

367/1 0.008

367/3 0.008

358 0.036

359/1 0.024

360/1ख 0.028

383 0.012

477/1 0.032

425 0.012

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला-जशपुर

(ख) तहसील-पथलगांव

(ग) नगर/ग्राम-सूरजगढ़

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.852 हेक्टेयर

(1)	(2)
427	0.120
426/1	0.092
435/1	0.016
494	0.020
479/1	0.020
520/430	0.008
474/1क	0.052
474/1ख	0.040
योग	26
	0.852

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घरजियांबथान जलाशय योजना की दांयी तट मुख्य नहर का शाखा नहर क्रमांक 03, 04 एवं 05 का अनिवार्य भू-अर्जन प्रकरण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पत्थलगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 8 दिसम्बर 2021

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 35/अ-82/2019-20.—चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

#### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-जशपुर
- (ख) तहसील-पत्थलगांव
- (ग) नगर/ग्राम-कोकियाखार
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.615 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
133/1क	0.154
140/2	0.057
143	0.081
134	0.093
142	0.105
137	0.085

(1)	(2)
140/1	0.040
योग	07
	0.615

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-ग्राम कोकियाखार स्थित गेरानाला जलाशय योजना के कोकियाखार शाखा नहर क्र. 07 का भू-अर्जन प्रकरण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पत्थलगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रितेश कुमार अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़  
एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व  
एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कबीरधाम, दिनांक 25 नवम्बर 2021

क्रमांक/194/201907080100060/अ-82 वर्ष 2018-19.—चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

#### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-बोड़ला
- (ग) नगर/ग्राम-सरईपतेरा, प.ह.नं. 44
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.028 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
97/35	0.0028
95/2	0.0028
95/1	0.0028
58/1	0.0028
94	0.0028

(1)	(2)	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-ग्राम सरईपतेरा में सरईपतेरा व्यपवर्तन योजनान्तर्गत नहर नाली निर्माण हेतु.
93/2	0.0028	
59/5	0.0028	
95/3	0.0028	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बोड़ला के न्यायालय में किया जा सकता है.
57/1	0.0028	
59/3	0.0028	
योग	0.028	छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रमेश कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

## विभाग प्रमुखों के आदेश

### कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, कोरबा (छ.ग.)

कोरबा, दिनांक 12 नवम्बर 2021

क्रमांक/13704/अधीक्षक/2021.—प्रशासनिक दृष्टिकोण से इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी कार्य विभाजन कार्यालयीन आदेश क्र. 12917/अधीक्षक/2021 कोरबा, दिनांक 13-10-2021 द्वारा श्री सुनील कुमार नायक, संयुक्त कलेक्टर कोरबा को अपर कलेक्टर का प्रभार सौंपा गया है. उक्त आदेश में सौंपे गये कार्यों के साथ-साथ निम्नांकित कार्य सौंपा जाता है :—

- अपीलीय अधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम
- हिन्दू विवाह अधिनियम के अधीन अधिकारी एवं विशेष विवाह अधिकारी

(ब) प्रभारी अधिकारी :—

- जनगणना

(स) कार्यालयीन नोडल अधिकारी :—

- भू-अर्जन/पुनर्वास
- रेल कारीडोर परियोजना

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

कोरबा, दिनांक 12 नवम्बर 2021

क्रमांक/13706/अधीक्षक/2021.—प्रशासनिक दृष्टिकोण से इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी कार्यालयीन कार्य विभाजन आदेश क्र. 12917/अधीक्षक/2021 कोरबा, दिनांक 13-10-2021 में श्रीमती सूर्यकिरण तिवारी अग्रवाल, संयुक्त कलेक्टर कोरबा का स्थानांतरण होने के फलस्वरूप इस कार्यालय से भारमुक्त होने के पश्चात् नीचे दर्शित कार्य श्री कौशल प्रसाद तेंदुलकर, डिप्टी कलेक्टर कोरबा को सौंपा जाता है :—

प्रभारी अधिकारी :—

- सिटी मजिस्ट्रेट
- भू-अभिलेख शाखा
- FRA एवं FCA प्रमाण पत्र जारी करने व उससे संबंधित प्रकरणों को निराकरण करने हेतु.
- सहायक अधीक्षक सामान्य/राजस्व आपदा प्रबंधन शाखा एवं कोविड 19 के प्रकरण (संबंधित शाखा की समस्त नस्ती अनुमोदन हेतु नोडल अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे.)
- भू-अर्जन/पुनर्वास
- रेल कारीडोर परियोजना



- भू-बंटन
- सहायक अधीक्षक राजस्व व कार्यालय निरीक्षण
- छ.ग. लोक सेवा गारण्टी अधिनियम 2011
- जिला पर्यावरण संरक्षण मण्डल (पर्यावरण)
- यातायात जिला सड़क सुरक्षा
- लोकसभा/राज्यसभा/विधानसभा के प्रश्नों का उत्तर समय पर तैयार कर नोडल अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे.
- लायसेंस शाखा/शस्त्र लायसेंस नवीनीकरण से संबंधित नस्ती स्वीकृति हेतु नोडल अधिकारी के माध्यम से कलेक्टर को प्रस्तुत करेंगे.
- जन सूचना अधिकारी — कार्यालय कलेक्टर कोरबा
- आयुक्त बिलासपुर संभाग, बिलासपुर के द्वारा ली जाने वाली मिटिंग एवं अन्य मिटिंग हेतु संधारित होने वाली जानकारी भेजना.

#### नोडल अधिकारी :—

- जिले में समय-समय में होने वाली मेगा कैम्प आयोजन हेतु
- लाईवलीहुड कालेज.
- नगर एवं ग्राम निवेश.
- (जिला शहरी विकास अभिकरण) डूडा.
- परिवहन विभाग
- जिला पंजीयक
- उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं
- समाज कल्याण विभाग एवं दिव्यांग
- औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा
- जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र
- जल संसाधन विभाग
- सार्वजनिक उपक्रमों से समन्वय संबंधी कार्य
- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

कोरबा, दिनांक 12 नवम्बर 2021

क्रमांक/13708/अधीक्षक/2021.—प्रशासनिक दृष्टिकोण से इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी कार्यालयीन कार्य विभाजन आदेश क्र. 12917/अधीक्षक/2021 कोरबा, दिनांक 13-10-2021 द्वारा श्री संजय कुमार मरकाम, डिप्टी कलेक्टर कोरबा को सौंपे गये कार्यों के साथ-साथ, समय-सीमा बैठक की सम्पूर्ण जानकारी का प्रभारी अधिकारी का दायित्व सौंपा जाता है.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

कोरबा, दिनांक 12 नवम्बर 2021

क्रमांक/13710/अधीक्षक/2021.—कार्यालयीन आदेश क्र./12917/अधीक्षक/2021, कोरबा दिनांक 13-10-2021 के द्वारा जिला मुख्यालय में पदस्थ अपर कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर के मध्य कार्य विभाजन किया गया है उक्त आदेश में आंशिक संशोधन कर जिला मुख्यालय में पदस्थ आयुक्त नगर पालिक निगम कोरबा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कोरबा, अपर कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर की अनुपस्थिति/अनुपलब्धता में लिंक आफिसर की व्यवस्था निम्नानुसार रहेगी :—

क्र.	अधिकारी का नाम व पदनाम	संयोजन अधिकारी का नाम
(1)	(2)	(3)
1.	आयुक्त नगर पालिक निगम, कोरबा	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कोरबा
2.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, कोरबा	आयुक्त नगर पालिक निगम, कोरबा

(1)	(2)	(3)
3.	श्री सुनील कुमार नायक, संयुक्त कलेक्टर, कोरबा	श्री अवध सिंह राणा, संयुक्त कलेक्टर, कोरबा
4.	श्री अवध सिंह राणा, संयुक्त कलेक्टर, कोरबा	श्री भरोसाराम ठाकुर, डिप्टी कलेक्टर, कोरबा
5.	श्री भरोसाराम ठाकुर, डिप्टी कलेक्टर, कोरबा	श्री अवध सिंह राणा, संयुक्त कलेक्टर, कोरबा
6.	श्री कौशल प्रसाद तेंदुलकर, डिप्टी कलेक्टर, कोरबा	श्री संजय मरकाम, डिप्टी कलेक्टर, कोरबा
7.	श्री संजय मरकाम, डिप्टी कलेक्टर, कोरबा	श्री कौशल प्रसाद तेंदुलकर, डिप्टी कलेक्टर, कोरबा

1. यदि किसी कारणवश प्रभारी/लिंक अधिकारी मुख्यालय में उपस्थित न हो तो ऐसी स्थिति में मुख्यालय में उपस्थित अधिकारी कार्य संपादित करेंगे.

2. उक्त संयोजन अधिकारी केवल कलेक्टर कार्यालय के शाखाओं के लिए ही रहेगा.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

रानू साहू  
कलेक्टर.

### कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर, छत्तीसगढ़

बिलासपुर, दिनांक 16 दिसम्बर 2021

प्ररूप-पांच  
(नियम 11 देखिये)

#### वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र के अंतिम प्रकाशन का प्रारूप

क्रमांक/5009/व.भू.उ.प्र./न.ग्रा.नि./2021.—बिल्हा निवेश क्षेत्र के लिए वर्तमान भूमि उपयोग हेतु मानचित्र को छत्तीसगढ़, नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 15 की उप-धारा (1) के अधीन छत्तीसगढ़ राजपत्र दिनांक 13-08-2021 में प्रकाशित किया गया था एवं उक्त धारा की उप-धारा (2) के उपबंधों के अधीन जनता से आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित किये गये. समस्त ऐसे व्यक्तियों को, जिन्होंने आपत्ति या सुझाव, उपांतरण प्रस्तुत किए हैं, अपेक्षित विचारण उसमें किया गया है.

यतः उपरोक्त निवेश क्षेत्र के लिए वर्तमान भूमि उपयोग हेतु मानचित्र, उक्त अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा (3) के अधीन एतद्वारा, अंगीकृत किया जाता है एवं इस सूचना की प्रति उक्त अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा (4) के अनुसरण में “छत्तीसगढ़ राजपत्र” में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है. जो इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि उक्त मानचित्र सम्यक् रूप से तैयार तथा अंगीकृत कर लिया गया है. उक्त अंगीकृत मानचित्र की प्रति छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस के लिए कार्यालयीन समय के दौरान निरीक्षण हेतु निम्नलिखित कार्यालयों में उपलब्ध रहेगी :—

1. आयुक्त बिलासपुर संभाग, बिलासपुर (छ.ग.)
2. जिला कलेक्टर, जिला बिलासपुर (छ.ग.)
3. नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर (छ.ग.)
4. नगर पंचायत बिल्हा, जिला बिलासपुर (छ.ग.)

FORM-V  
(See rule 11)

#### Form for final publication of existing land use map

No. 5009/ELU/TCP/2021.—The existing land use map for Bilha, was published under sub-section (1) of section 15 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) in the Chhattisgarh Gazette dated 13-08-2021 and objections and suggestions were invited from the public under the provision of sub-

section (2) of the said section. After giving reasonable opportunity of hearing to all such persons who have filed the objection or suggestion, modifications as considered, are made therein.

Now, the existing land use maps for the above planning area is hereby adopted under sub-section (3) of section 15 of the said अधिनियम and a copy of the notice is also sent for its publication in "Chhattisgarh Gazette" under provision of sub-section (4) of section 15 of the said अधिनियम, which shall be conclusive evidence of the fact that the above maps has been duly prepared and adopted. The said adopted maps shall be available for inspection during office hours for a period of 15 days from the publication of the notice in chhattisgarh Gazette in the following offices :—

1. Commissioner, Division Bilaspur, Dist. Bilaspur (C.G.)
2. District Collector, Dist. Bilaspur (C.G.)
3. Town and Country Planning, Bilaspur (C.G.)
4. Nagar Panchayat Bilha, Dist. Bilaspur (C.G.)

विनीत नायर,  
संयुक्त संचालक.

**कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़, रायपुर**  
(खण्ड-3, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर)

नवा रायपुर, दिनांक 12 नवम्बर 2021

क्रमांक/21/प्रवर्तन/श्र.आ./2020-21/490.—मैं अमृत कुमार खलखो, श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ शासन के श्रम विभागीय आदेश 473/7258/16, दिनांक 24 जनवरी, 1961 द्वारा प्रदत्त, शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, एतद्वारा छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 (क्रमांक 25 सन् 1958) की धारा 40 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक-2 में दर्शाये गये श्रमायुक्त संगठन में कार्यरत व्यक्तियों को सारणी के स्तम्भ क्रमांक-3 में दर्शाये गये स्थानीय क्षेत्रों के लिये "निरीक्षक" नियुक्त करता हूँ :—

क्र. (1)	कर्मचारी का नाम (2)	पदनाम (3)	अधिकार क्षेत्र (4)
1.	श्री दीपक चन्द्राकर	श्रम निरीक्षक	संपूर्ण राज्य में सभी स्थानीय क्षेत्रों एवं सभी प्रकार के संस्थानों के लिए जिन पर यह अधिनियम लागू होता है.
2.	श्री डीलेन्द्र कुमार चौधरी	श्रम निरीक्षक	—तदैव—
3.	श्री गौरव महोबिया	श्रम निरीक्षक	—तदैव—
4.	श्री राहुल मेहरा	श्रम निरीक्षक	—तदैव—
5.	श्री गोपी सिंह	श्रम निरीक्षक	—तदैव—
6.	कु. अर्चना ध्रुव	श्रम निरीक्षक	—तदैव—
7.	कु. भावना कौशिक	श्रम निरीक्षक	—तदैव—
8.	श्री सतानंद नाग	श्रम निरीक्षक	—तदैव—
9.	श्री विजेन्द्र चन्द्राकर	उप श्रम निरीक्षक	—तदैव—
10.	श्री डोलामणी मांझी	उप श्रम निरीक्षक	—तदैव—
11.	श्री दीपक सोनवानी	उप श्रम निरीक्षक	—तदैव—
12.	कु. कीर्ति डहाट	उप श्रम निरीक्षक	—तदैव—
13.	श्रीमती ममता सिंह कुरीम	उप श्रम निरीक्षक	—तदैव—
14.	श्री तोष कुमार सोरी	उप श्रम निरीक्षक	—तदैव—
15.	श्रीमती पुष्पांजली चौहान	उप श्रम निरीक्षक	—तदैव—
16.	श्रीमती उमा सोनवानी	उप श्रम निरीक्षक	—तदैव—
17.	श्री सुरेश कुमार जाल	उप श्रम निरीक्षक	—तदैव—

अमृत कुमार खलखो,  
श्रमायुक्त.

**कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़**  
**शास्त्री चौक, पुराना मंत्रालय परिसर, रायपुर**

रायपुर, दिनांक 18 अगस्त 2021

क्रमांक 21/चार/निरर्हित/2018-21/2067.—विधानसभा निर्वाचन-2018 के दौरान निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी द्वारा लेखा दाखिल करने में असफल रहे, श्री उमेन्द सिंह पोट्टाम, श्री खेलन सिंह कोर्चे, श्री लालजी मार्को, श्री गुलाब सिंह पैकरा एवं चन्द्रभान सिंह श्याम, जिला-बिलासपुर को तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित घोषित किये जाने संबंधी भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के आदेश संख्या छ.ग.-वि.स./पूर्व अनु.-1/24/2018, दिनांक 28 जुलाई, 2021 सर्व साधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है।

( के. सी. देवसेनापति )  
 अति. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

**भारत निर्वाचन आयोग**  
**निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001**

नई दिल्ली, तारीख 28 जुलाई, 2021—6 श्रावण, 1943 (शक)

सं. छ.ग.-वि.स./पूर्व अनु.-1/24/2018.—यतः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य से विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2018 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./66/2018 दिनांक 6 अक्टूबर, 2018 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 11 दिसम्बर, 2018 थी।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है।

और यतः, 24-मरवाही (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 11 दिसम्बर, 2018 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 जनवरी, 2019 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बिलासपुर जिला, छत्तीसगढ़ द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ द्वारा अपने दिनांक 29 जनवरी, 2019 के पत्र सं. 21/चार/वि.स.चु./ई.ई.एम./2019/85 के जरिए अग्रेषित दिनांक 11 जनवरी, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार श्री उमेन्द सिंह पोट्टाम, जो छत्तीसगढ़ के 24-मरवाही (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले शिवसेना अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बिलासपुर जिला, छत्तीसगढ़ और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री उमेन्द सिंह पोट्टाम को कारण बताओ नोटिस दिनांक 3 सितम्बर, 2019 को जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 3 सितम्बर 2019 के उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री उमेन्द सिंह पोट्टाम को निर्देश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री उमेन्द सिंह पोट्टाम द्वारा 7 नवम्बर, 2019 को प्राप्त किया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, बिलासपुर द्वारा अपने दिनांक 8 जनवरी, 2020 के पत्र सं. नि.प./वि.स.नि.-2018/व्यय लेखा/2020/4402 के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बिलासपुर द्वारा अपने दिनांक 7 जुलाई, 2020 के पत्र सं. नि.प./वि.स.नि./व्यय लेखा/2019/141 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री उमेन्द सिंह पोटांम ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री उमेन्द सिंह पोटांम निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :—

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति —

- (i) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- (ii) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरहित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि छत्तीसगढ़ राज्य के 24-मरवाही (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से छत्तीसगढ़ राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 में निर्वाचन लड़ने वाले शिवसेना अभ्यर्थी श्री उमेन्द सिंह पोटांम, ग्राम-तौली, पोस्ट-डोंगरिया, तहसील-पेण्डारोड, जिला-बिलासपुर, छत्तीसगढ़ को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरहित है।

आदेश से,

हस्ता./-

( नरेन्द्र ना. बुटोलिया )

वरिष्ठ प्रधान सचिव,  
भारत निर्वाचन आयोग.

## ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

New Delhi, dated 28th July, 2021—6 Sravana, 1943 (Saka)

No. CG-LA/ES-I/24/2018.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 was announced by Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/66/2018 dated 6th October, 2018. As per the schedule, Date of Counting was 11th December, 2018.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including 24-Marwahi (ST) Assembly Constituency on 11th December, 2018. As such the last date for lodging of account of election expenses was 10th January, 2019.

AND WHEREAS, as per the report dated 11th January, 2019 submitted by the District Election Officer, Bilaspur District, Chhattisgarh and forwarded by Chief Electoral Officer, Chhattisgarh vide letter No. 21/4/LAEle/EEM/2019/85, dated 29th January, 2019, Sh. Umend Singh Pottam, Shiv Sena, contesting candidate from 24-Marwahi (ST) Assembly Constituency of Chhattisgarh, has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Bilaspur District, Chhattisgarh and the Chief Electoral Officer, Chhattisgarh, a show Cause Notice, dated 3rd September, 2019 was issued by Election Commission of India under sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to Sh. Umend Singh Pottam, for non-submission of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice, dated 3rd September, 2019, Sh. Umend Singh Pottam, was directed to submit his representation in writing in the Commission explaining the reason for non-submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by Sh. Umend Singh Pottam, on 7th November, 2019. Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, Bilaspur vide his letter No. Ele.P/LAEle.-2018/Exp./2020/4402 dated 8th January, 2020.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, Bilaspur vide his letter No. Ele.P/LAEle/Exp./2019/141 dated 7th July, 2020, has stated that Sh. Umend Singh Pottam, has not submitted any representation or his account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission satisfied that Sh. Umend Singh Pottam, has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the people Act, 1951 Stipulates that :—

“If the Election Commission is satisfied that a person:

- (a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act, and
- (b) Has no good reason or justification for the failure the Election Commission shall by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the under;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Sh. Umend Singh Pottam, resident of Village-Tauli, PO.-Dongariya, Tahsil-Pendra Road, District-Bilaspur, Chhattisgarh and the contesting Shiv sena candidate for General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 from 24-Marwahi (ST) Assembly Constituency of the state of Chhattisgarh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,

Sd/-  
(NARENDRA N. BUTOLIA)  
Senior Principal Secretary,  
Election Commission of India.

नई दिल्ली, तारीख 28 जुलाई, 2021—6 श्रावण, 1943 (शक)

सं. छ.ग.-वि.स./पूर्व अनु.-1/24/2018.—यतः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य से विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2018 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./66/2018 दिनांक 6 अक्टूबर, 2018 के जरिए की गई थी. कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 11 दिसम्बर, 2018 थी.

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है

और यतः, 24-मरवाही (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 11 दिसम्बर, 2018 को घोषित किए गए थे. इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 जनवरी, 2019 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बिलासपुर जिला, छत्तीसगढ़ द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ द्वारा अपने दिनांक 29 जनवरी, 2019 के पत्र सं. 21/चार/वि.स.चु./ई.ई.एम./2019/85 के जरिए अग्रेषित दिनांक 11 जनवरी, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार श्री खेलन सिंह कोर्चे, जो छत्तीसगढ़ के 24-मरवाही (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अम्बेडकराईट पार्टी आफ इंडिया अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं.

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बिलासपुर जिला, छत्तीसगढ़ और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री खेलन सिंह कोर्चे को कारण बताओ नोटिस दिनांक 3 सितम्बर, 2019 को जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 3 सितम्बर 2019 के उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री खेलन सिंह कोर्चे को निर्देश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री खेलन सिंह कोर्चे द्वारा 7 नवम्बर, 2019 को प्राप्त किया था. अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, बिलासपुर द्वारा अपने दिनांक 8 जनवरी, 2020 के पत्र सं. नि.प./वि.स.नि.-2018/व्यय लेखा/2020/4402 के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बिलासपुर द्वारा अपने दिनांक 7 जुलाई, 2020 के पत्र सं. नि.प./वि.स.नि./व्यय लेखा/2019/141 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री खेलन सिंह कोर्चे ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है. इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री खेलन सिंह कोर्चे निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :—

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति —

- (i) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- (ii) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरहिंत घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहिंत होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि छत्तीसगढ़ राज्य के 24-मरवाही (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से छत्तीसगढ़ राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 में निर्वाचन लड़ने वाले अम्बेडकराईट पार्टी आफ इंडिया अभ्यर्थी श्री खेलन सिंह कोर्चे, ग्राम-जिल्दा, पोस्ट-कोडगार, तहसील-पेण्ड्रा, जिला-बिलासपुर, छत्तीसगढ़, को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरहित है।

आदेश से,

हस्ता./-

( नरेन्द्र ना. बुटोलिया )

वरिष्ठ प्रधान सचिव,  
भारत निर्वाचन आयोग.

New Delhi, dated 28th July, 2021—6 Sravana, 1943 (Saka)

No. CG-LA/ES-I/24/2018.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 was announced by Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/66/2018 dated 6th October, 2018. As per the schedule, Date of Counting was 11th December, 2018.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including 24-Marwahi (ST) Assembly Constituency on 11th December, 2018. As such the last date for lodging of account of election expenses was 10th January, 2019.

AND WHEREAS, as per the report dated 10th January, 2019 submitted by the District Election Officer, Bilaspur District, Chhattisgarh and forwarded by Chief Electoral Officer, Chhattisgarh vide letter No. 21/4/LAEle/EEM/2019/85, dated 29th January, 2019, Sh. Khelan Singh Korche, Ambedkarite Party of India, contesting candidate from 24-Marwahi (ST) Assembly Constituency of Chhattisgarh, has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Bilaspur District, Chhattisgarh and the Chief Electoral Officer, Chhattisgarh, a show Cause Notice, dated 3rd September, 2019 was issued by Election Commission of India under sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to Sh. Khelan Singh Korche, for non-submission of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice, dated 3rd September, 2019, Sh. Khelan Singh Korche, was directed to submit his representation in writing in the Commission explaining the reason for non-submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by Sh. Khelan Singh Korche, on 7th November, 2019. Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, Bilaspur vide his letter No. Ele.P/LAEle.-2018/Exp./2020/4402 dated 8th January, 2020.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, Bilaspur vide his letter No. Ele.P/LAEle/Exp./2019/141 dated 7th July, 2020, has stated that Sh. Khelan Singh Korche, has not submitted any representation or his account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;



AND WHEREAS, the Commission satisfied that Sh. Khelan Singh Korche, has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the people Act, 1951 Stipulates that :—

“If the Election Commission is satisfied that a person:

- (i) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act, and
- (ii) Has no good reason or justification for the failure the Election Commission shall by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the under;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Sh. Khelan Singh Korche, resident of Village-Jilda, PO-Kodgar, Tahsil-Pendra Road, District-Bilaspur, Chhattisgarh and the contesting Ambedkarite Party of India candidate for General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 from 24-Marwahi (ST) Assembly Constituency of the state of Chhattisgarh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,

Sd/-  
(NARENDRA N. BUTOLIA)  
Senior Principal Secretary,  
Election Commission of India.

नई दिल्ली, तारीख 28 जुलाई, 2021—6 श्रावण, 1943 (शक)

सं. छ.ग.-वि.स./पूर्व अनु.-1/24/2018.—यतः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य से विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2018 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./66/2018 दिनांक 6 अक्टूबर, 2018 के जरिए की गई थी. कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 11 दिसम्बर, 2018 थी.

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है

और यतः, 24-मरवाही (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 11 दिसम्बर, 2018 को घोषित किए गए थे. इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 जनवरी, 2019 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बिलासपुर जिला, छत्तीसगढ़ द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ द्वारा अपने दिनांक 29 जनवरी, 2019 के पत्र सं. 21/चार/वि.स.चु./ई.ई.एम./2019/85 के जरिए अग्रेषित दिनांक 11 जनवरी, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार श्री लालजी मार्को, जो छत्तीसगढ़ के 24-मरवाही (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले आम आदमी पार्टी अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं.

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बिलासपुर जिला, छत्तीसगढ़ और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री लालजी मार्को को कारण बताओ नोटिस दिनांक 3 सितम्बर, 2019 को जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 3 सितम्बर 2019 के उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री लालजी मार्को को निर्देश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री लालजी मार्को द्वारा 7 नवम्बर, 2019 को प्राप्त किया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, बिलासपुर द्वारा अपने दिनांक 8 जनवरी, 2020 के पत्र सं. नि.प./वि.स.नि.-2018/व्यय लेखा/2020/4402 के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बिलासपुर द्वारा अपने दिनांक 7 जुलाई, 2020 के पत्र सं. नि.प./वि.स.नि./व्यय लेखा/2019/141 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री लालजी मार्को ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री लालजी मार्को निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :—

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति —

- (i) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- (ii) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि छत्तीसगढ़ राज्य के 24-मरवाही (अ.ज.जा.) विधान सभा क्षेत्र से छत्तीसगढ़ राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 में निर्वाचन लड़ने वाले आम आदमी पार्टी अभ्यर्थी श्री लालजी मार्को, मकान नं. 25 झिरनापोड़ी माझेटोला, ग्राम-झिरनापोड़ी, तहसील-पेण्ड्रारोड, गौरेला जिला-बिलासपुर, छत्तीसगढ़ को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

आदेश से,

हस्ता./—

( नरेन्द्र ना. बुटोलिया )

वरिष्ठ प्रधान सचिव,  
भारत निर्वाचन आयोग.

New Delhi, dated 28th July, 2021—6 Sravana, 1943 (Saka)

No. CG-LA/ES-I/24/2018.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 was announced by Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/66/2018 dated 6th October, 2018. As per the schedule, Date of Counting was 11th December, 2018.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including 24-Marwahi (ST) Assembly Constituency on 11th December, 2018. As such the last date for lodging of account of election expenses was 10th January, 2019.

AND WHEREAS, as per the report dated 11th January, 2019 submitted by the District Election Officer, Bilaspur District, Chhattisgarh and forwarded by Chief Electoral Officer, Chhattisgarh vide letter No. 21/4/LAEle/EEM/2019/85, dated 29th January, 2019, Sh. Lalji Marko, Aam Aadmi Party, contesting candidate from 24-Marwahi (ST) Assembly Constituency of Chhattisgarh, has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Bilaspur District, Chhattisgarh and the Chief Electoral Officer, Chhattisgarh, a show Cause Notice, dated 3rd September, 2019 was issued by Election Commission of India under sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to Sh. Lalji Marko, for non-submission of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice, dated 3rd September, 2019, Sh. Lalji Marko, was directed to submit his representation in writing in the Commission explaining the reason for non-submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by Sh. Lalji Marko, on 7th November, 2019. Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, Bilaspur vide his letter No. Ele.P/LAEle.-2018/Exp./2020/4402 dated 8th January, 2020.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, Bilaspur vide his letter No. Ele.P/LAEle/Exp./2019/141 dated 7th July, 2020, has stated that Sh. Lalji Marko, has not submitted any representation or his account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission satisfied that Sh. Lalji Marko, has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the people Act, 1951 Stipulates that :—

“If the Election Commission is satisfied that a person:

- (i) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act, and
- (ii) Has no good reason or justification for the failure the Election Commission shall by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the under;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Sh. Lalji Marko, resident of House No. 25, Jhirnapodi Majhetola Village-Jhirnapodi, Tahsil-Pendra Road, Gaurela District-Bilaspur, Chhattisgarh and the contesting Aam Aadmi Party candidate for General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 from 24-Marwahi (ST) Assembly Constituency of the state of Chhattisgarh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,

Sd/-  
(NARENDRA N. BUTOLIA)  
Senior Principal Secretary,  
Election Commission of India.

नई दिल्ली, तारीख 28 जुलाई, 2021—6 श्रावण, 1943 (शक)

सं. छ.ग.-वि.स./पूर्व अनु.-1/24/2018.—यतः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य से विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2018 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./66/2018 दिनांक 6 अक्टूबर, 2018 के जरिए की गई थी. कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 11 दिसम्बर, 2018 थी.

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है

और यतः, 24-मरवाही (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 11 दिसम्बर, 2018 को घोषित किए गए थे. इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 जनवरी, 2019 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बिलासपुर जिला, छत्तीसगढ़ द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ द्वारा अपने दिनांक 29 जनवरी, 2019 के पत्र सं. 21/चार/वि.स.चु./ई.ई.एम./2019/85 के जरिए अग्रेषित दिनांक 11 जनवरी, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार श्री गुलाब सिंह पैकरा, जो छत्तीसगढ़ के 24-मरवाही (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं.

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बिलासपुर जिला, छत्तीसगढ़ और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री गुलाब सिंह पैकरा को कारण बताओ नोटिस दिनांक 3 सितम्बर, 2019 को जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 3 सितम्बर 2019 के उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री गुलाब सिंह पैकरा को निर्देश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री गुलाब सिंह पैकरा द्वारा 7 नवम्बर, 2019 को प्राप्त किया था. अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, बिलासपुर द्वारा अपने दिनांक 8 जनवरी, 2020 के पत्र सं. नि.प./वि.स.नि.-2018/व्यय लेखा/2020/4402 के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बिलासपुर द्वारा अपने दिनांक 7 जुलाई, 2020 के पत्र सं. नि.प./वि.स.नि./व्यय लेखा/2019/141 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री गुलाब सिंह पैकरा ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है. इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरान्त भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री गुलाब सिंह पैकरा निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :—

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति —

- (i) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- (ii) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि छत्तीसगढ़ राज्य के 24-मरवाही (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से छत्तीसगढ़ राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 में निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी श्री गुलाब सिंह पैकरा, ग्राम-आमाडाड, तहसील-पेण्ड्रा, जिला-बिलासपुर, छत्तीसगढ़ को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है.

आदेश से,

हस्ता./-

( नरेन्द्र ना. बुटोलिया )

वरिष्ठ प्रधान सचिव,  
भारत निर्वाचन आयोग.

New Delhi, dated 28th July, 2021—6 Sravana, 1943 (Saka)

No. CG-LA/ES-I/24/2018.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 was announced by Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/66/2018 dated 6th October, 2018. As per the schedule, Date of Counting was 11th December, 2018.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including 24-Marwahi (ST) Assembly Constituency on 11th December, 2018. As such the last date for lodging of account of election expenses was 10th January, 2019.

AND WHEREAS, as per the report dated 11th January, 2019 submitted by the District Election Officer, Bilaspur District, Chhattisgarh and forwarded by Chief Electoral Officer, Chhattisgarh vide letter No. 21/4/LAEle/EEM/2019/85, dated 29th January, 2019, Sh. Gulab Singh Paikra, Independent, contesting candidate from 24-Marwahi (ST) Assembly Constituency of Chhattisgarh, has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Bilaspur District, Chhattisgarh and the Chief Electoral Officer, Chhattisgarh, a show Cause Notice, dated 3rd September, 2019 was issued by Election Commission of India under sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to Sh. Gulab Singh Paikra, for non-submission of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice, dated 3rd September, 2019, Sh. Gulab Singh Paikra, was directed to submit his representation in writing in the Commission explaining the reason for non-submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by Sh. Gulab Singh Paikra, on 7th November, 2019. Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, Bilaspur vide his letter No. Ele.P./LAEle.-2018/Exp./2020/4402 dated 8th January, 2020.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, Bilaspur vide his letter No. Ele.P./LAEle/Exp./2019/141 dated 7th July, 2020, has stated that Sh. Gulab Singh Paikra, has not submitted any representation or his account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission satisfied that Sh. Gulab Singh Paikra, has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the people Act, 1951 Stipulates that :—

“If the Election Commission is satisfied that a person:

- (i) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act, and
- (ii) Has no good reason or justification for the failure the Election Commission shall by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the under;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Sh. Gulab Singh Paikra, resident of Village-Amadand, Teh.-Pendra, District-Bilaspur, Chhattisgarh and the contesting Independent candidate for General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 from 24-Marwahi (ST) Assembly Constituency of the state of Chhattisgarh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,

Sd/-  
(NARENDRA N. BUTOLIA)  
Senior Principal Secretary,  
Election Commission of India.

नई दिल्ली, तारीख 28 जुलाई, 2021—6 श्रावण, 1943 (शक)

सं. छ.ग.-वि.स./पूर्व अनु.-1/24/2018.—यतः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य से विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2018 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./66/2018 दिनांक 6 अक्टूबर, 2018 के जरिए की गई थी. कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 11 दिसम्बर, 2018 थी.

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है

और यतः, 24-मरवाही (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 11 दिसम्बर, 2018 को घोषित किए गए थे. इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 जनवरी, 2019 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बिलासपुर जिला, छत्तीसगढ़ द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ द्वारा अपने दिनांक 29 जनवरी, 2019 के पत्र सं. 21/चार/वि.स.चु./ई.ई.एम./2019/85 के जरिए अग्रेषित दिनांक 11 जनवरी, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार श्री चन्द्रभान सिंह श्याम, जो छत्तीसगढ़ के 24-मरवाही (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं.

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बिलासपुर जिला, छत्तीसगढ़ और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री चन्द्रभान सिंह श्याम को कारण बताओ नोटिस दिनांक 3 सितम्बर, 2019 को जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 3 सितम्बर 2019 के उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री चन्द्रभान सिंह श्याम को निर्देश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री चन्द्रभान सिंह श्याम द्वारा 7 नवम्बर, 2019 को प्राप्त किया था. अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, बिलासपुर द्वारा अपने दिनांक 8 जनवरी, 2020 के पत्र सं. नि.प./वि.स.नि.-2018/व्यय लेखा/2020/4402 के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बिलासपुर द्वारा अपने दिनांक 7 जुलाई, 2020 के पत्र सं. नि.प./वि.स.नि./व्यय लेखा/2019/141 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री चन्द्रभान सिंह श्याम ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है. इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री चन्द्रभान सिंह श्याम निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :—

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति —

- (i) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- (ii) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरहित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि छत्तीसगढ़ राज्य के 24-मरवाही (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से छत्तीसगढ़ राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 में निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी श्री चन्द्रभान सिंह श्याम, ग्राम-रूमगा, तहसील-मरवाही, जिला-बिलासपुर, छत्तीसगढ़ को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरहित है.

आदेश से,

हस्ता./-

( नरेन्द्र ना. बुटोलिया )

वरिष्ठ प्रधान सचिव,  
भारत निर्वाचन आयोग.

New Delhi, dated 28th July, 2021—6 Sravana, 1943 (Saka)

No. CG-LA/ES-I/24/2018.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 was announced by Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/66/2018 dated 6th October, 2018. As per the schedule, Date of Counting was 11th December, 2018.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including 24-Marwahi (ST) Assembly Constituency on 11th December, 2018. As such the last date for lodging of account of election expenses was 10th January, 2019.

AND WHEREAS, as per the report dated 11th January, 2019 submitted by the District Election Officer, Bilaspur District, Chhattisgarh and forwarded by Chief Electoral Officer, Chhattisgarh vide letter No. 21/4/LAEle/EEM/2019/85, dated 29th January, 2019, Sh. Chandrabhan Singh Shayam, Independent, contesting candidate from 24-Marwahi (ST) Assembly Constituency of Chhattisgarh, has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Bilaspur District, Chhattisgarh and the Chief Electoral Officer, Chhattisgarh, a show Cause Notice, dated 3rd September, 2019 was issued by Election Commission of India under sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to Sh. Chandrabhan Singh Shayam, for non-submission of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice, dated 3rd September, 2019, Sh. Chandrabhan Singh Shayam, was directed to submit his representation in writing in the Commission explaining the reason for non-submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by Sh. Chandrabhan Singh Shayam, on 7th November, 2019. Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, Bilaspur vide his letter No. Ele.P/LAEle.-2018/Exp./2020/4402 dated 8th January, 2020.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, Bilaspur vide his letter No. Ele.P/LAEle/Exp./2019/141 dated 7th July, 2020, has stated that Sh. Chandrabhan Singh Shayam, has not submitted any representation or his account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission satisfied that Sh. Chandrabhan Singh Shayam, has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the people Act, 1951 Stipulates that :—

“If the Election Commission is satisfied that a person:

- (i) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act, and
- (ii) Has no good reason or justification for the failure the Election Commission shall by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the under;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Sh. Chandrabhan Singh Shayam, resident of Village-Rumga, Tahsil-Marwahi Road, District-Bilaspur, Chhattisgarh and the contesting Independent candidate for General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 from 24-Marwahi (ST) Assembly Constituency of the state of Chhattisgarh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,

Sd/-  
(NARENDRA N. BUTOLIA)  
Senior Principal Secretary,  
Election Commission of India.